

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 629वीं बैठक दिनांक 14/03/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9322/2022 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, , G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, (M.P.), Prior Environment Clearance for Patai Sand Quarry an area of 24.00 ha. (79,887 cum per annum) At Khasra No.- 337,284 Village-Patai,Tehsil-Deori, District-Raisen (M.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.- 337,284 Village-Patai,Tehsil-Deori, District-Raisen (M.P.) 24.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 595वीं दिनांक 22/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसका कुछ भाग (लगभग 5 प्रतिशत) पानी में डूबा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो भाग पानी में डूबा है, वहाँ खनन प्रस्तावित नहीं है तथा प्रस्तुतीकरण में 1.40 हे. का नॉन माईनिंग जोन छोड़ा गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन योजना के "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की

गई है जिसके पेज नं. 68 के सरल क्रमांक-52 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । साथ ही तालिका-20 (पेज नं.-68) के सरल क्रमांक-52 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-4,32,000 घनमीटर उल्लेखित है जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 79,887 घनमीटर की हेतु आवेदन किया गया है । अनुमोदित माइन प्लान के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 79,887 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है । समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा । इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 79,887 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थाएं स्थापित की जाये । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है । अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमनानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तरी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयवधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरान्त यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान रोजगार, रोड का चौड़ीकरण, वृक्षारोपण, गांव से बाहर से परिवहन इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा तथा रेत का परिवहन गांव के रास्ते से नहीं किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 79,887 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 38.77 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 06.52 लाख प्रति वर्ष ।
3. यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माइनिंग की जाये ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 18.70 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लिप्स, गटायन एवं औषधीय पौधों जैसे कालमेघ, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी इत्यादि के बीजों का छिड़काव तथा स्थानीय घास का रोपण । 4-5 पंक्ति - कटंग बांस) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	15700 2000 1000
2	ग्राम- पतई , इंद्रप्रस्थ, दिघावन, पिपराणी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	9,900
3	परिवहन मार्ग (750 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबी, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	150
	सरकारी माध्यमिक विद्यालय पतई में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक , नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि ।	50
		योग	28,800

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु.में)
सरपंच के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के लिए ग्राम- पतई के प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी ।	40,000 / -
ग्राम पतई में समस्त ग्रामीण और बच्चों के लियें साल में दो बार स्वास्थ्य शिविर के जांच के लिए रक्तचाप, मधुमेह एवं मुख स्वच्छता का आयोजन किया जायेगा ।	30,000 / -
रास्ते की मरम्मत हेतु आर्थिक मदद	20,000 / -
योग	90,000 / -

2. Case No 9324/2022 M/s Pushpa Enterprises, Prop. Shri Anand Tamrakar, , G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, (M.P.), Prior Environment Clearance for Bharkachha Kalan Sand Quarry in an area of 12.0 ha. (1,50,000 cum per annum) At Khasra No.-614 near Village- Bharkachha Kalan, Tehsil- Badi, District- Raisen (M.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.-614 near Village- Bharkachha Kalan, Tehsil- Badi, District- Raisen (M.P.) 12.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 595वीं दिनांक 22/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन योजना के "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-67 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-2,16,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,50,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। साथ ही तालिका-20 (पेज नं.-67) के सरल क्रमांक-37 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-2,16,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,50,00 घनमीटर की हेतु आवेदन किया गया है । अनुमोदित माइन प्लॉन के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 1,50,00 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है । समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा । इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 1,50,00 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थाएँ स्थापित की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति

की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, पंचायत की सड़क का उपयोग रेत परिवहन हेतु नहीं किया जावेग, सड़को पर जल छिड़काव किया, फसल खराब होने की संभावना, रेत परिवहन हेतु अलग रास्ता बनायेगा, बच्चों के शिक्षा में सहयोग एवं वृक्षारोपण इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा, रेत का परिवहन गांव के रास्ते से नहीं किया जायेगा तथा ग्रामीण सड़क के रखरखाव का कार्य किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 1,50,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 32.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 07.95 लाख प्रति वर्ष ।
3. यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माईनिंग की जाये ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 12.85 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे :-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लिप्स, गटायन एवं औषधीय पौधों जैसे कालमेघ, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी इत्यादि के बीजों का छिड़काव तथा स्थानीय घास का रोपण। 4-5 पंक्ति — कटंग बांस) 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, लसोड़ा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातिया)	9,850 2000 1000
2	ग्राम— भारकच्छ कलां के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
	परिवहन मार्ग में (771 m)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबी, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	500
3	ग्राम भारकच्छ कलां में प्राथमिक विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक , नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
		योग	14,400

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.में)
गांव में सड़कों के मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता ।	20,000 /—
बच्चों की शिक्षा के लिए गांव भारकच्छ कलां के प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी।	40,000 /—
सरपंच के माध्यम से गांव के विकास कार्य मे सहयोग किया जाएगा	50,000 /—
एम्बुलेंस तथा चिकित्सीय व्यवस्था की सुविधा दी जाएगी तथा उपचार हेतु अधिकतम 1,00,000 की राशि दी जाएगी ।	100,000 /—
सरपंच के माध्यम से परिक्रमावासियों के शेड के निर्माण के लिए सहयोग किया जाएगा	50,000 /—
योग	2,60,000 /—

3. Case No 9323/2022 M/s Shri Anand Tamrakar, Prop. , G-7, 8, Deendayal Parisar, E-2, Arera Colony, Dist. Bhopal, (M.P.) Prior Environment Clearance for Goramchuwai 2 Sand Quarry an area of 20.00 ha. (300174 cum per annum) At Khasra No.- 475, Village- Goramchhuwai -2 Tehsil- Badi, District-Raisen (M.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.- 475, Village-Patai, Tehsil-Deori, District-Raisen (M.P.) 20.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 595वीं दिनांक 22/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन योजना के "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-67 के सरल क्रमांक-42 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-3,60,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,00,174 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। साथ ही तालिका-20 (पेज नं.-67) के सरल क्रमांक-42 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत)-3,60,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,00,174 घनमीटर की हेतु आवेदन किया गया है। अनुमोदित माइन प्लॉन के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 3,00,174 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से काफी कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है। समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 3,00,174 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थाएँ स्थापित की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल उड़ने से फसल खराब होगी, गांव के कच्चे रास्तों में बरसात में एवं सिंचाई से कीचड़ की समस्या इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा, रेत का परिवहन गांव के रास्ते से नहीं किया जायेगा तथा ग्रामीण सड़क के रखरखाव का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 3,00,174 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 41.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 07.55 लाख प्रति वर्ष।
3. यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माईनिंग की जाये।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 21.80 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लिप्स, गटायन एवं औषधीय पौधों जैसे कालमेघ, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी इत्यादि के बीजों का छिड़काव तथा स्थानीय घास का रोपण। 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	15000 5000 1800
2	ग्राम- गोरामछुवाई के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
3	परिवहन मार्ग में (500 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबी, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	150
	गोरामछुवाई सरकारी विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
		योग	24,000

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.45 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गांव गोरामछुवाई के प्राथमिक विद्यालय में एक प्रिंटर और कंप्यूटर के साथ टेबल की व्यवस्था करायी जाएगी	50,000/-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

रेत परिवहन मार्ग के मरम्मत हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा	20,000 /—
रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में हैबिटेशन डेवेलोपमेंट के लिए	60,000 /—
ग्राम वासायो के स्वस्थ परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जायेगा	15,000 /—
रास्ते की मरम्मत हेतु बालू फ्री में दिया जाएगा	
योग	1,45,000 /—

4. Case No 9332/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 15.0 ha. (120000 Cum per annum) (Khasra No. 398), Village - Andiya, Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 398), Village - Andiya, Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP) 15.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 599वीं दिनांक 08/10/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के कुछ भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वह रेत निकलने के कारण ऐसा दिख रहा है तथा खदान का वह भाग जिसमें पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सिर्फ 6.124 हे. क्षेत्र में खनन किया जायेगा तथा स्वीकृत गहराई 02 मीटर के हिसाब से 1,20,000 घन मीटर प्रतिवर्ष रेत निकाली जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-67 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-2,70,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,20,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। खनिज अधिकारी के पत्र क्र०. 1080 दिनांक 15/09/2022 में लेख किया गया है कि समूह क्र०. 1 की कुल खदानों के Coordinates में भिन्नता के कारण डी.एस.आर. के Coordinates को मान्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है। समिति की

अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 1,20,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थाएँ स्थापित की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तरी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा प्रदूषण, धूल, ध्वनि प्रदूषण, ट्रकों की 24 घंटे आवाजाही से ग्रामीणों को परेशानी, मुख्य सड़क परिवहन होने से खराब इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा, रेत का परिवहन गांव के रास्ते से नहीं किया जायेगा, PUC Certified ट्रकों/डम्परों का प्रयोग किया जायेगा तथा ग्रामीण सड़क के रखरखाव का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 1,20,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 31.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 07.11 लाख प्रति वर्ष।
3. यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माईनिंग की जाये।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 15.73 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लिप्स, गटायन एवं औषधीय पौधों जैसे कालमेघ, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी इत्यादि के बीजों का छिड़काव तथा स्थानीय घास का रोपण। 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	11000 3730 1000
2	अंडिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
	परिवहन मार्ग में (600 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबी, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	220
3	अंडिया के प्राथमिक विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक , नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
		योग	18,000

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अंडिया गांव के सरपंच के माध्यम से मंदिर, धर्मशाला और स्कूल के विकास के लिए।	70,000/-
अंडिया गांव के स्कूल में सोलर लाइट उपलब्ध कराने के लिए।	30,000/-
प्राथमिक विद्यालय अंडिया में 01 कम्प्यूटर, प्रिंटर उपलब्ध कराने के लिए।	50,000/-
रेत परिवहन मार्ग के मरम्मत हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा।	20,000/-
योग	1,70,000/-

5. Case No 9333/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 14.0 ha. (2,00,000 Cum per annum) (Khasra No. 225/1), Village - Satrawan-1, Tehsil - Baraily, Dist. Raisen (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 225/1), Village - Satrawan-1, Tehsil - Baraily, Dist. Raisen (MP) 14.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 599वीं दिनांक 08/10/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान से वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-65 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2,52,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2,00,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माईनिंग की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व इस जिले का टेंडर संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो गई थी, जिस कारण मात्रा में अंतर आ रहा है। समिति की अनुशंसा है कि इस स्थिति में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई मात्रा का पुनः निर्धारण जिला खनिज अधिकारी द्वारा किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार खनिज विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत मात्रा 2,00,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, जिस हेतु मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थाएँ स्थापित की जाये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वाहनों नियंत्रित गति सीमा में संचालन, गांव से लेकर नर्मदा नदी घाट तक वृक्षारोपण, टेढोनी नदी के किनारे पर वृक्षारोपण, सड़क का चौड़ीकरण एवं पक्की सड़क का निर्माण एवं गांव की आंगनवाड़ी में खिलौनों, कुर्सी तथा अन्य सामग्री इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम. पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा, रेत का परिवहन गांव के रास्ते से नहीं किया जायेगा, PUC Certified ट्रकों/डम्परों का प्रयोग किया जायेगा, ग्रामीण सड़क के रखरखाव का कार्य किया जायेगा, नर्मदा नदी एवं टेढोनी नदी के किनारे पर वृक्षारोपण तथा आंगनवाड़ी में आवश्यक खिलौना,

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

कुर्सी एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 2,00,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 27.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 06.31 लाख प्रति वर्ष।
3. यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माईनिंग की जाये।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 14.63 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों (नर्मदा घाट से लेकर टेढोनी नदी तक) पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लिप्स, गटायन एवं औषधीय पौधों जैसे कालमेघ, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी इत्यादि के बीजों का छिड़काव तथा स्थानीय घास का रोपण। 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	10000 3630 1000
2	टेढोनी नदी के किनारे पर वृक्षारोपण	करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	सतरावन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
4	परिवहन मार्ग में (650 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबी, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	120
	सतरावन के प्राथमिक	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम,	50

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

विद्यालय में वितरण हेतु	सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	
	योग	16,800

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.में)
ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए साल में दो बार चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा	15,000 /—
गांव बगलवाड़ा राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर और 10 डेस्क और बेंच की व्यवस्था करायी जाएगी	60,000 /—
गांव में सड़कों के मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता ।	50,000 /—
आंगनवाड़ी में आवश्यक खिलौना, कुर्सी एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था	50,000 /—
योग	1,75,000 /—

6. Case No 9716/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Lasangaon Sand Mine in an area of 14.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 2/1, 2/2/1/k, 46), Village-Lasangaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2/1, 2/2/1/k, 46), Village-Lasangaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 14.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 370 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 14.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह नर्मदा नदी के पास स्थित खोदू भरू प्रकृति की खदान है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन एक ही भाग की गूगल इमेज दिख रही है जबकि खदान तीन भागों में स्वीकृत है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा तीनों भागों की गूगल इमेज अपलोड की गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में एक ही दिख रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष

है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाये तथा प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर कुछ पेड़ हैं अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. यह नर्मदा नदी के पास स्थित खोदू भरू प्रकृति की खदान है तथा खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है, अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाये तथा प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

7. Case No 9717/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Kapsi Sand Mine in an area of 10.3660 ha. (1000 Cum per annum) (Khasra No. 1, 236, 582, 592, 685), Village-Kapsi, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 236, 582, 592, 685), Village-Kapsi, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 10.3660 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 368 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 10.366 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत उरी बागनी नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान क्षेत्र नदी के कन्फ्लूएंस के अपस्ट्रीम में स्थित है तथा पांच भागों में आवंटित है। लीज के पश्चिमी किनारे से नदी की धारा निकल रही है तथा एक स्टॉप डेम खदान क्षेत्र से 752 मी. डाउन स्ट्रीम में स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि ऑन लाईन एक ही भाग की गूगल इमेज दिख रही है जबकि खदान पांच भागों में स्वीकृत है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पांचों भागों की गूगल इमेज अपलोड की गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में एक ही दिख रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ तथा संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पश्चिमी किनारे से नदी की धारा निकल रही है, एक स्टॉप डेम खदान क्षेत्र से 752 मी. डाउन स्ट्रीम में स्थित है तथा खदान क्षेत्र नदी में पांच भागों में आवंटित है, जिसमें से खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ मय संरक्षण योजना के ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।

2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
5. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. Case No 9718/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Birlai Sand Mine in an area of 8.00 ha. (1200 Cum per annum) (Khasra No. 83, 319), Village- Birlai, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 83, 319), Village- Birlai, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 8.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 367 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 8.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।

यह रेत उरी बागनी नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के दक्षिणी-पूर्वी भाग से नदी की धारा निकल रही है तथा ऑन लाईन एक ही भाग की गूगल इमेज दिख रही है जबकि खदान दो भागों में स्वीकृत है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा दोनो भागों की गूगल इमेज अपलोड की गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में एक ही दिख रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष है । अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

औचित्य के साथ तथा संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1200 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिणी-पूर्वी भाग से नदी की धारा निकल रही है तथा खदान दो भागों में स्वीकृत है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ तथा संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
5. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

9. Case No 9723/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Pipalagadi Sand Mine in an area of 26.50 ha. (3650 Cum per annum) (Khasra No. 205/1, 21/2/1, 228/1/1, 229/1/1, 229/9/1/1, 229/9/4, 36/1), Village- Pipalagadi, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 205/1, 21/2/1, 228/1/1, 229/1/1, 229/9/1/1, 229/9/4, 36/1), Village- Pipalagadi, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 26.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 366 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 26.50 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह नर्मदा नदी की खोदू भरू खदान है जो पांच भागों में आवंटित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि ऑनलाईन एक ही भाग की गूगल इमेज दिख रही है जबकि खदान पांच भागों में स्वीकृत है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पांचों भागों की गूगल इमेज अपलोड की गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में एक ही दिख रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 3650 घनमीटर प्रतिवर्ष है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का औचित्य तथा प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-3650 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3650 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. यह नर्मदा नदी के पास पांच भागों में आवंटित खोदू भरू खदान है जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 3650 घनमीटर प्रतिवर्ष है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का औचित्य तथा प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

10. Case No 9725/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Rajpura Sand Mine in an area of 11.00 ha. (1500 Cum per annum) (Khasra No. 38, 40, 41/1), Village-Rajpura, Tehsil-Manawar, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 38, 40, 41/1), Village-Rajpura, Tehsil-Manawar, District-Dhar (MP) 11.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 374 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 11.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह खोदू भरू खदान है जो मौसमी नदी के समीप स्थित है तथा यह नदी दक्षिण दिशा में नर्मदा में मिलती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खोदू भरू खदान के दक्षिण-पूर्व दिशा से आकर एक नाला नदी में मिल रहा है एवं खदान के दक्षिणी सीमा नाले के समीप है तथा उक्त नाले पर एक पुल निर्मित है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-126 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1500 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1500 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

1. यह खोदू भरू खदान है जिसके दक्षिण-पूर्व दिशा से आकर एक नाला इसमें मिल रहा है एवं खदान के दक्षिणी सीमा नाले के समीप है तथा नाले पर एक पुल निर्मित है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
5. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

11. Case No 9726/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Morgadi Sand Mine in an area of 7.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 132/1), Village- Morgadi, Tehsil- Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 132/1), Village- Morgadi, Tehsil- Dharampuri, District-Dhar (MP) 7.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 378 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 7.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह नर्मदा नदी की खोदू भरू खदान है जो नर्मदा नदी से लगभग 70 मी. की दूरी पर स्थित है तथा खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

नं-125 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. गूगल इमेज अनुसार अनुसार यह खोदू भरू खदान नर्मदा नदी से लगभग 70 मी. की दूरी पर स्थित है अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

12. Case No 9727/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Banki Sand Mine in an area of 5.782 ha. (1250 Cum per annum) (Khasra No. 251, 351), Village- Banki, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 251, 351), Village- Banki, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 5.782 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर,

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

(खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 380 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 5.782 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत भूरी नदी पर दो भागों में स्वीकृत है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-1250 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1250 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
4. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

13. Case No 9728/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Shahpura Sand Mine in an area of 9.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 118/1, 118/2), Village-Shahpura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 118/1, 118/2), Village-Shahpura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 9.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स केएटिव

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 357 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 9.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह खोदू भरू खदान नर्मदा नदी के समीप स्थित है अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-1000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, जो अधिक है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. गूगल इमेज अनुसार अनुसार यह खोदू भरू खदान नर्मदा नदी के समीप स्थित है अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

14. Case No 9729/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Nanoda Sand Mine in an area of 8.00 ha.

(2000 Cum per annum) (Khasra No. 1, 340), Village-Nanoda, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 340), Village-Nanoda, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 8.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 382 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इस खदान का क्षेत्रफल 8.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान भूरी नदी पर स्थित है जो दो भागों में आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में लगभग 472 मीटर की दूरी पर एक स्टॉप डेम स्थित है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में लगभग 472 मीटर की दूरी पर एक स्टॉप डेम स्थित है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
5. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

6. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

15. Case No 9719/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Kurdigpura Sand Mine in an area of 5.00 ha. (280 Cum per annum) (Khasra No. 309), Village- Kurdigpura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 309), Village- Kurdigpura, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 364 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान उरी बागनी नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-280 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 280 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 28 मी. पर एक स्टॉप डेम एवं 200 मी. पर एक पक्का रोड ब्रिज है तथा दक्षिण दिशा से लीज एरिया के मध्य में एक मौसमी नाला आकर मिल रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्टॉप डेम एवं 200 मी. पर एक पक्का रोड ब्रिज के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 500 मीटर का सेटवेक छोड़ा गया है तथा मौसमी नाला के दोनो ओर भी 50 मीटर का सेटवेक छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.2316 हे. क्षेत्र खनन हेतु उत्तर दिशा में उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है, जिससे स्वीकृत मात्रा 280 घन मीटर/वर्ष का उत्पादन किया जा सकता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 280 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 280 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.19 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 230 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the farmers whose land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	230

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
One Wheel Chari to be provided to nearest PHCs	10,000.00

16. Case No 9721/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bharadpur Sand Mine in an area of 4.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 214/1, 214/2), Village-Bharadpur, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 214/1, 214/2), Village-Bharadpur, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 379 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बन्ने नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-31 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र का उत्तर-पश्चिम दिशा एवं दक्षिण पश्चिम किनारा जलमग्न है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलमग्न होने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में उक्त भाग को नॉन माइनिंग एरिया दोनों ओर छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.8422 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उत्तर दिशा में उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 2,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर-पूर्वी दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई. आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 2000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.43 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.48 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 850 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers whose land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	850

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

Activities	Cost in Rs
Three complete bed and one warmer machine to be provided to nearest PHCs	1.00

17. Case No 9722/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bhandakho Sand Mine in an area of 3.00 ha. (350 Cum per annum) (Khasra No. 136), Village-Bhandakho, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 136), Village-Bhandakho, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 358 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 3.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान कारम नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र का उत्तर-पूर्वी दिशा एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा जलमग्न है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलमग्न होने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में उक्त भाग को नॉन माइनिंग एरिया दोनों ओर छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.2940 हे. का क्षेत्र खनन हेतु दक्षिण दिशा में उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 350 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-126 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-350 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 350 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन दक्षिण-पश्चिमी दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 350 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 350 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.15 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.24 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 300 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:—

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who's land are near to the river bank and evacuation route.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	300

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :—

Activities	Cost in Rs
Three complete bed at Nearest PHC	0.50

18. Case No 9724/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Akhada Sand Mine in an area of 0.875 ha. (175 Cum per annum) (Khasra No. - 75), Village-Akhada, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 75, Village-Akhada, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 0.875 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 362 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 0.875 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान प्राकृतिक नाले में स्थित है जो कि पूर्णतः जलमग्न है इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो गूगल इमेज दर्शित हो रही है वह मानसून के समय की है इस कारण जलमग्न दिख रही है यदि पुरानी गूगल इमेज (मार्च 2016) का अवलोकन करें तो पायेंगे कि आवंटित खनन क्षेत्र में रेत उपलब्ध है। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी दिशा में एक छोटी जल रोकने की संरचना बनी हुई है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जल रोकने की संरचना के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 250 मीटर को सेटवेक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है जिस कारण 0.1369 हे. क्षेत्र खनन योग्य है जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 175 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-175 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 175 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 175 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 175 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.19 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 140 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	140

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Activities	Cost in Rs
One wheel chair to provide to nearest PHCs	0.10

19. Case No 9730/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Dehariya Sand Mine in an area of 2.00 ha. (600 Cum per annum) (Khasra No. 48, 77), Village-Dehariya, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 48, 77), Village-Dehariya, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 373 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सुकाद नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-126 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल-600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 600 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड ब्रिज नदी के अपस्ट्रीम में है तथा पूर्व दिशा में भी एक दूसरा रोड ब्रिज नदी के डाउन स्ट्रीम में है छोटा सा सिविल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दोनों दिशाओं में पक्का रोड ब्रिज के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 250 मीटर एवं 500 मी. का सेटबैक दोनों ओर छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.1475 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 600 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

क्षेत्र दो ब्लॉक में आवंटित है किन्तु ऑनलाइन एक ही ब्लॉक दर्शित हो रहा है, जो संभवतः सॉफ्टवेयर के कारण हुआ है क्योंकि अनुमोदित खनन योजना, डी.एस.आर. तथा प्रस्तुतीकरण में हमारे द्वारा दो ब्लॉक दिखाये गये हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 600 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 600 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.22 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 150 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	150

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Activities	Cost in Rs
Two wheel chair to be provided to nearest PHCs	0.20

20. Case No 9731/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Gaadiyadaggad Sand Mine in an area of 1.051 ha. (550 Cum per annum) (Khasra No. 141, 149), Village- Gaadiyadaggad, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 141, 149), Village- Gaadiyadaggad, Tehsil-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

Dharampuri, District-Dhar (MP) 1.051 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरूमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 359 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 1.051 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नाले में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-126 के सरल क्रमांक-31 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-550 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 550 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर दिशा में लीज एरिया के अंदर जल रोकने की दो संरचनायें स्थित हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दोनों दिशाओं जल रोकने की दो संरचनाओं के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 100 मीटर का सेटबैक दोनों ओर छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.2316 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 550 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर-पूर्वी दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 550 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 550 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.32 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 230 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	230

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Activities	Cost in Rs
Two wheel chair to be provided to nearest PHCs	0.20

21. Case No 9732/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Nimola Sand Mine in an area of 7.00 ha. (9000 Cum per annum) (Khasra No. 181/2), Village- Nimola, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP). (ToR).

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 181/2), Village- Nimola, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 7.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 376 दिनांक 18/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 7.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान खोदुभरू (नर्मदा नदी) है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। गूगल इमेज अनुसार अनुसार यह खोदू भरू खदान नर्मदा नदी के समीप स्थित है अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-9,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. गूगल इमेज अनुसार अनुसार यह खोदू भरू खदान नर्मदा नदी के समीप स्थित है अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण संरक्षण योजना सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

22. Case No 9737/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-

466331, Prior Environment Clearance for Kothida Sand Mine in an area of 4.00 ha. (400 Cum per annum) (Khasra No. 84), Village-Kothida, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 84), Village-Kothida, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 361 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान कारम नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-126 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल-400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 400 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी जिस कारण लगभग 2.10 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है जो स्वीकृत मात्रा मात्र 400 घन मीटर हेतु पर्याप्त है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 400 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 400 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.13 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.19 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 260 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	260

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Activities	Cost in Rs
Two wheel chair to be provided to nearest PHCs	0.20

23. Case No 9738/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bagwanya Sand Mine in an area of 0.24 ha. (250 Cum per annum) (Khasra No. 768), Village-Bagwanya, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 768), Village-Bagwanya, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 0.24 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 360 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 0.24 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नाले में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-126 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-250 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 250 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र नाले पर स्थित है वर्तमान में उपलब्ध गूगल इमेज अनुसार जलमग्न है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलमग्न होने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में सेटवेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है, जिस कारण लगभग 0.1053 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है तथा पूर्व की गूगल इमेज मई 2022 अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 250 घन मीटर है रेत आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 250 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 250 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.19 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 100 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	100

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Activities	Cost in Rs
One wheel chair to be provided to nearest PHCs	0.10

24. Case No 9753/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Palvat Sand Mine in an area of 5.00 ha.

(1,000 Cum per annum) (Khasra No. 1), Village-Palvat, Tehsil-Dhahi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village-Palvat, Tehsil-Dhahi, District-Dhar (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरुमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 365 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सुक्कड नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबल 35 के 60 प्रतिशत माइनेवल पोटेन्शियल-1200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र अधिकांशतः जलमग्न है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलमग्न होने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में सेटवेक दोनो ओर 4.16 हे. का प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है, जिस कारण 5.0 हे. में से लगभग 0.8452 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 1,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 1000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 1000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.43 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.23 लाख प्रति वर्ष।

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 850 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:—

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	850

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :—

Activities	Cost in Rs
One wheel chair and two complete bed to be provided to nearest PHCs	0.30

25. Case No 9740/2023 M/s National Energy Trading and Services Limited, Director, Shri Vinod Kumar Godavarthi, R/o Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, Hyderabad, Rangareddi, TG-500089 Prior Environment Clearance for Loniya Sand Mine in an area of 1.115 ha. (15,000 Cum per annum) (Khasra No. - 179), Village-Loniya, Tehsil-Ghodadongri, District-Betul (M.P.).

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 179), Village- Loniya, Tehsil-Ghodadongri, District-Betul (MP) 1.115 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 241 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 1.115 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान तवा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-47 के सरल क्रमांक-01 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-36000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 m³/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र आंशिक रूप से जलमग्न है, तथा लीज एरिया के दक्षिणी भाग में तवा नदी में दूसरी नदी आकर मिल रही है जिसके संदर्भ में

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलमग्न एवं संगम होने के कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में सेटवेक छोड़ा गया है तथा जिस कारण लगभग 0.6690 हे. का क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 15,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 15,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 4.50 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.75 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 700 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	700

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
One wheel chair, two complete bed and one warmer to be provided to nearest PHCs	1,00,000

26. Case No 9741/2023 M/s National Energy Trading and Services Limited, Director, Shri Vinod Kumar Godavarthi, R/o Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, Hyderabad, Rangareddi, TG-500089 Prior Environment Clearance for Guwadi Sand Mine in an area of 2.50 ha. (42120 Cum per annum) (Khasra No. 19), Village-Guwadi, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 19), Village-Guwadi, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वांटिटी इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 241 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 2.50 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान तवा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-48 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-58,968 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 70,200 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जो 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल से अधिक है।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी किनारा आंशिक रूप से जलमग्न है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलमग्न होने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में सेटवेक छोड़ा गया है तथा जिस कारण लगभग 1.63 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 70200 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर-पूर्वी दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 42,120 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.50 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.25 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank and evacuation route.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	1700

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Issues	Cost in Rs
Two wheel chair, five complete bed and one Warmer to be provided to nearest PHCs	2.00

27. Case No 9742/2023 M/s National Energy Trading and Services Limited, Director, Shri Vinod Kumar Godavarthi, R/o Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, Hyderabad, Rangareddi, TG-500089 Prior Environment Clearance for Ratamati Sand Mine in an area of 2.550 ha. (21600 Cum per annum) (Khasra No. 1), Village-Ratamati, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village-Ratamati, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) 2.550 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 मार्च 2023

हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 241 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 2.550 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान ताप्ती नदी में स्थित है तथा गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 90 मीटर पर वनक्षेत्र परिलक्षित हो रहा है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 241 दिनांक 08/02/2023 के अनुसार कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) बेतूल के प्रतिवेदन क्रमांक 3319 दिनांक 13/04/16 अनुसार स्वीकृत रेत खदान वन सीमा से 250 मीटर के अंदर नहीं है। अतः संबंधित वनमंडलाधिकारी से इसकी पुष्टि कराई जाना उचित होगा।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च 2023

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Movable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘D’

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under “Ujjwala Yojna” to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP’s commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिपल जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

629वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 मार्च 2023

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10?5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर